



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1779/2023

Gagan Kumar S/o Shri Jagmohan, Aged About 23 Years, R/o Village Ramnagar, Tehsil Weir, District Bharatpur (Raj.).

----Claimant/Appellant

Versus

1. Jugal Singh Chaudhary S/o Shri Natthi Singh, R/o Garoli, Presently R/o Mahi Colony, Gadhi, Police Station Gadhi, District Banswara (Raj.) (Owner Of Indica Vista No. RJ-03-CA-1860)
2. Vishambhar S/o Shri Chhiddi Singh, R/o Garoli, Tehsil Deeg, District Bharatpur (Raj.) (Driver Of Indica Vista No. RJ-03-CA-1860)
3. The Oriental Insurance Company Ltd., Through Branch Manager, The Oriental Insurance Company Ltd., Nayi Mandi Station Road, Bharatpur (Raj.) (Insurance Company Of Indica Vista No. RJ-03-CA-1860)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Navankur Dubey, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Amar Nath Pareek, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

06/05/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर (राज.) (जिसे आगे 'अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-562/2016 (200/2015), बउनवान गगन कुमार बनाम जुगल सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2023 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 43,06,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को कुल 5,57,718/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय



ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए उसकी मासिक आय 4,914/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि अपीलार्थी को कुशल श्रमिक माना जाकर उसकी मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर पर आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी को कुल 32.3 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता कारित होना बताया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में कोई समुचित राशि नहीं दिलवाई गयी है तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 32.3 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be



compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in *Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd.* explained "just compensation" in the following words:

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.05.2014 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 15 वर्ष की आयु का होना बताते हुए अध्ययनरत बालक होना बताया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 4,914/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।

8. मोटर वाहन दुर्घटना के उन मामलों में जहां बच्चे की मृत्यु कारित हो जाती हो या वह आहत हो जाता हो, वहां उस बालक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित किये जाने की सुस्थापित विधि है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Hitesh Nagjibhai**



Patel Vs. Bababhai Nagjibhai Rabari & Anr., Civil Appeal No. 10278/2025 (Arising Out of SLP (C) No. 14444/2025) में यह

मत व्यक्त किया है कि :—

"9. On the aspect of monthly income of the minor appellant, we are inclined to interfere with the judgment and order of the Courts below. In the present case, it is evident that the Courts below have failed to take into account the monthly income of the appellant while determining the quantum of compensation. It is now a well-entrenched and consistently reiterated principle of law that a minor child who suffers death or permanent disability in a motor vehicle accident, cannot be placed in the same category as a non-earning individual for the purposes of assessing the amount of compensation because the child was not engaged in gainful employment at the time of the accident. In such a case, the computation of compensation under the head of loss of income ought to be made by adopting, at the very least, the minimum wages payable to a skilled workman as notified for the relevant period in the respective State where the cause of action arises. The said observation was rendered by this Court, in **Kajal v. Jagdish Chand and Ors.3**, and **Baby Sakshi Greola v. Manzoor Ahmad Simon and Anr.4**.

14. As can be seen, there is a great difference between the compensation as awarded by the Courts below and the compensation payable as per law. We are constrained to observe that appeals to the High Court as well as to this Court were entirely avoidable, since the law had been amply clarified well before the order of the Tribunal was made on 17.10.2021 by way of the judgment rendered by this Court in **Kajal** (supra) decided on 05.02.2020. Both the Courts were duty-bound to keep abreast with the law as clarified by this Court, ensuring that the judgments and orders



passed by them **are** entirely in order therewith.

15. For the purpose of emphasis, it is again clarified here that when a Tribunal or the High Court in appeal, is concerned with the case involving a child having suffered injury or having passed away, the calculation of loss of income necessarily has to be made on the matrix of minimum wages payable to a skilled worker in the respective State at the relevant point of time. It is our hope that this restatement helps avoiding such errors and thereby obviates the necessity of this Court's interference, applying well-established principles of law."

9. ऐसी स्थिति में हम, **Hitesh Nagjibhai Patel (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में भी आहत बालक को वक्त घटना कुशल श्रमिक होना मानते हुए घटना की तिथि 09.05.2014 को प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी दैनिक आय 209/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $209 \times 30 = 6,270/—$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना आहत बालक की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 6,270/— रुपये में 40 प्रतिशत अर्थात् 2,508/— रुपये की बढ़ोतरी करते हुए अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 8,778/— रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

10. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित होना बताया गया है, जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 32.3 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-64 के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। इस प्रकार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षति में



32.3 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 32 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय 8,778/— रुपये का 32 प्रतिशत 2,809/— रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की **कुल क्षति $2,809 \times 12 \times 18 = 6,06,744$ /— रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा इलाज पर व्यय की गयी राशि के मद में 23,672/— रुपये, 05 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 2,500/— रुपये तथा यातायात व परिवहन की मद में 34,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई है, इनमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 17,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है जो कम है। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम, 32,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में हम, अपीलार्थी को 32,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 5,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। अतः पौष्टिक आहार



की मद में हम, 10,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	6,06,744 /-
2.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	23,672 /-
3.	05 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	2,500 /-
4.	यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में	34,000 /-
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	32,000 /-
6.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	32,000 /-
7.	पौष्टिक आहार की मद में	10,000 /-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		7,40,916 /-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि		5,57,718 /-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		1,83,198 /-

16. तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **5,57,718/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **7,40,916/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

17. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

18. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

19. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J